भारत सरकार
योजना मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2533
दिनांक 11.12.2024 को उत्तर देने के लिए

राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठकें

2533. श्री हनुमान बेनीवाल:

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) का क्या उद्देश्य है;
- (ख) एनडीसी की कुल कितनी बैठकें आयोजित की गई हैं तथा अब तक लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन में कितनी प्रगति हुई है;
- (ग) नीति आयोग के गठन के पश्चात एनडीसी की प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और
- (घ) एनडीसी के उद्देश्यों की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कोई स्वतंत्र निगरानी तंत्र न बनाने के क्या कारण हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय;

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) योजना मंत्रालय एवं

राज्यमंत्री, संस्कृति मंत्रालय

(राव इंद्रजीत सिंह)

- (क) से (घ): राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) की स्थापना वर्ष 1952 में तत्कालीन योजना आयोग के तत्वावधान में की गई थी, जिसका उद्देश्य योजना के लिए संसाधनों के आकलन सहित, राष्ट्रीय योजना के निर्माण हेतु दिशानिर्देश निर्धारित करना; योजना आयोग द्वारा तैयार की गई राष्ट्रीय योजना पर विचार करना; राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करने वाले सामाजिक और आर्थिक नीति से

संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार करना; और समय-समय पर योजना संबंधी कामकाज की समीक्षा करना एवं राष्ट्रीय योजना में निर्धारित लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक उपायों की सिफारिश करना था। एनडीसी की अध्यक्षता भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा की गई थी और इसमें केंद्रीय मंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री तथा संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक एवं तत्कालीन योजना आयोग के सदस्य शामिल थे।

नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प के माध्यम से किया गया था, जिसने भारत सरकार के प्रमुख नीति थिंक टैंक के रूप में पूर्ववर्ती योजना आयोग की जगह ली, जिसका उद्देश्य केंद्र, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को प्रासंगिक कार्यनीतिक, दिशात्मक नीतिगत इनपुट और तकनीकी सलाह प्रदान करना और राष्ट्रीय विकास कार्यसूची को पूरा करने की दिशा में राज्यों को एक साथ लाना है। नीति आयोग की अपनी शासी परिषद् है, जिसे 16 फरवरी 2015 को कैबिनेट सचिवालय द्वारा जारी एक अधिसूचना के माध्यम से स्थापित किया गया था और 19 फरवरी 2021 को इसका पुनर्गठन किया गया था। भारत के माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में शासी परिषद के तहत सभी राज्यों और विधानसभा सहित संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री, अन्य संघ राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपाल, नीति आयोग के उपाध्यक्ष और सदस्य तथा विशेष आमंत्रित सदस्य शामिल हैं। शासी परिषद को राष्ट्रीय प्राथमिकताओं का साझा दृष्टिकोण विकसित करने तथा राष्ट्रीय विकास की रूपरेखा तैयार करने का कार्य सौंपा गया है।

अब तक माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में शासी परिषद की 9 बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं और अंतिम बैठक 27 जुलाई, 2024 को हुई थी। शासी परिषद के उद्देश्यों को विधिवत पूरा करना सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त निगरानी तंत्र मौजूद हैं।